



शशि प्रभा गौतम

सहायक प्रोफेसर— समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, जखिखनी, वाराणसी।

सारांश— वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया के तीव्र विस्तार ने सूचना के प्रसार को अत्यधिक सरल एवं व्यापक बना दिया है, किंतु इसके साथ ही “झूठी खबरें” एवं “भ्रामक सूचना” जैसी गंभीर समस्याएँ भी उभरकर सामने आई हैं। प्रस्तुत शोध वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में फेक न्यूज के स्वरूप, प्रसार, कारणों तथा प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि डिजिटल साक्षरता की कमी, एल्गोरिदमिक संरचना, सामाजिक—मानसिक प्रवृत्तियाँ तथा राजनीतिक हित फेक न्यूज के प्रसार के प्रमुख कारक हैं। इसके अतिरिक्त, भ्रामक सूचनाओं का प्रसार सामाजिक अस्थिरता, सामुदायिक तनाव, आर्थिक हानि तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जन्म देता है। विशेष रूप से युवाओं में बिना सत्यापन के सूचना साझा करने की प्रवृत्ति इस समस्या को और जटिल बनाती है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि फेक न्यूज केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक बहुआयामी सामाजिक चुनौती है। इसके समाधान हेतु डिजिटल एवं मीडिया साक्षरता के प्रसार, तकनीकी नियंत्रण तंत्र तथा प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिससे एक सुरक्षित एवं उत्तरदायी डिजिटल वातावरण का निर्माण किया जा सके।

मुख्य शब्द— फेक न्यूज, भ्रामक सूचना, डिजिटल साक्षरता, सोशल मीडिया, साइबर सुरक्षा, सूचना समाज

प्रस्तावना

वर्तमान डिजिटल युग में सूचना का प्रसार अत्यंत तीव्र और व्यापक हो गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जहाँ सूचना तक पहुँच को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर झूठी खबरें एवं भ्रामक सूचना जैसी समस्याएँ भी गंभीर रूप से उभरकर सामने आई हैं। विशेष रूप से वर्ष 2018 के आसपास यह मुद्दा वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक चर्चित रहा, जब सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं के प्रसार ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर प्रभाव डालना शुरू किया। फेक न्यूज से तात्पर्य ऐसी झूठी या भ्रामक सूचनाओं से है, जिन्हें जानबूझकर सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि मिसइन्फॉर्मेशन वह गलत या अपूर्ण जानकारी होती है, जो अनजाने में फैलती है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर “उद्देश्य” का होता है फेक न्यूज में धोखा देने की मंशा होती है, जबकि मिसइन्फॉर्मेशन में ऐसा आवश्यक नहीं होता।

झूठी खबर ऐसी निर्मित अथवा परिवर्तित सूचना, जो सत्य के विपरीत होते हुए भी उसे वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है और जिसका उद्देश्य जनसमूह को भ्रमित करना होता है। मिथ्या सूचना अनजाने में



प्रसारित गलत अथवा अधूरी जानकारी, जिसमें भ्रामकता तो होती है, परंतु उसके पीछे कोई जानबूझकर की गई दुर्भावना नहीं होती। दुष्प्रचारपूर्वनिर्णयित एवं उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रसारित असत्य या विकृत सूचना, जिसका लक्ष्य जनमत को प्रभावित करना, भ्रम उत्पन्न करना अथवा वैचारिकधराजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर फेक न्यूज के प्रसार के प्रमुख माध्यम बन गए हैं। इन प्लेटफॉर्म की संरचना ऐसी होती है, जो सनसनीखेज और भावनात्मक सामग्री को अधिक तेजी से फैलाती है। परिणामस्वरूप, उपयोगकर्ता बिना सत्यापन के सूचनाओं को साझा कर देते हैं, जिससे गलत जानकारी व्यापक स्तर पर फैल जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ डिजिटल साक्षरता अपेक्षाकृत कम होती है, वहाँ यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

झूठी खबरें एवं भ्रामक सूचना के प्रसार के पीछे कई कारण कार्य करते हैं।

पहला, डिजिटल साक्षरता की कमी, लोग यह नहीं समझ पाते कि कौन-सी जानकारी विश्वसनीय है और कौन-सी नहीं।

दूसरा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, लोग उन सूचनाओं को अधिक स्वीकार करते हैं, जो उनकी पूर्व मान्यताओं के अनुरूप होती हैं।

तीसरा, तकनीकी कारण, सोशल मीडिया के प्रोग्राम आधारित (एल्गोरिद्म) ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं, जो अधिक सहभागिता प्राप्त करता है, भले ही वह सत्य हो या नहीं।

इसके प्रभाव अत्यंत व्यापक और गंभीर हैं। फेक न्यूज के कारण सामाजिक तनाव, अफवाहें और हिंसा की घटनाएँ तक उत्पन्न हो जाती हैं। कई मामलों में गलत सूचनाओं ने समुदायों के बीच अविश्वास और वैमनस्य को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है, क्योंकि चुनावों के दौरान भ्रामक सूचनाएँ मतदाताओं को भ्रमित कर सकती हैं। युवाओं के संदर्भ में, फेक न्यूज उनकी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे वे गलत दिशा में प्रेरित हो सकते हैं।

झूठी खबरें एवं भ्रामक सूचना आधुनिक डिजिटल समाज की एक गंभीर चुनौती है, जो केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक आयामों से जुड़ी हुई है। इसके प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी घटककृसरकार, तकनीकी संस्थाएँ, शिक्षा प्रणाली और नागरिककृ सामूहिक रूप से प्रयास करें, ताकि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण का निर्माण किया जा सके।



किन्तु इस प्रक्रिया ने एक नई चुनौती भी उत्पन्न कीक्यूठी खबरों और भ्रामक सूचनाओं का अनियंत्रित प्रसार। 2018 के आसपास यह समस्या वैश्विक स्तर पर एक "डिजिटल संकट" के रूप में उभरी।

फेक न्यूज का परिदृश्य

वर्तमान समय को सूचना क्रांति का युग कहा जाता है, जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संचार के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। आज सूचना का प्रसार अत्यंत तीव्र, सुलभ और व्यापक हो गया है। किन्तु इसी के साथ "फेक न्यूज" अर्थात् झूठी खबरें और भ्रामक सूचनाएँ एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई हैं (Allcott & Gentzkow, 2017)।

वैश्विक स्तर पर फेक न्यूज का प्रभाव विशेष रूप से 2010 के बाद अधिक स्पष्ट हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस के विस्तार ने सूचना के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया, परंतु इसके साथ ही गलत सूचनाओं के तीव्र प्रसार का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, झूठी खबरें सत्य समाचारों की तुलना में अधिक तेजी से फैलती हैं।

सोशल मीडिया तंत्र ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं, जो अधिक उपयोगकर्ता सहभागिता उत्पन्न करता है, चाहे वह सत्य हो या नहीं। इसके परिणामस्वरूप फेक न्यूज न केवल आम जनमानस को भ्रमित करती है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चुनावों को भी प्रभावित करती है (Lazer et al., 2018)।

हालाँकि, डिजिटल साक्षरता की कमी और सूचना के सत्यापन की प्रवृत्ति का अभाव इस समस्या को और बढ़ाता है। 2018 से पूर्व भारत में व्हाट्सएप जैसी सेवाओं के माध्यम से फैली अफवाहों के कारण भीड़ हिंसा जैसी घटनाएँ सामने आईं, जो फेक न्यूज के गंभीर सामाजिक प्रभाव को दर्शाती हैं, इसके अतिरिक्त, फेक न्यूज के प्रसार में मानवीय व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग अक्सर बिना सत्यापन के सूचनाओं को साझा कर देते हैं, जिससे भ्रामक सूचना तेजी से फैलती है। फेक न्यूज केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी सामाजिक चुनौती है, जिसमें तकनीकी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी आयाम शामिल हैं। इसके प्रभावी समाधान हेतु डिजिटल साक्षरता, मीडिया साक्षरता और सुदृढ़ नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिससे एक सुरक्षित और विश्वसनीय सूचना वातावरण का निर्माण किया जा सके।

झूठी खबरों का प्रभाव—झूठी खबरें एक बहुआयामी संरचनात्मक समस्या है, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत से लेकर वैश्विक स्तर तक देखा जा सकता है।

सामाजिक प्रभाव झूठी खबरों का सामाजिक प्रभाव अत्यंत गहरा और व्यापक होता है। इसके कारण समाज में अविश्वास, तनाव एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। UNESCO-2017 के अनुसार,



भ्रामक सूचनाएँ सामाजिक विश्वास को कमजोर करती हैं तथा सामुदायिक विभाजन को बढ़ावा देती हैं। जब लोग बार-बार गलत और भ्रामक सूचनाओं के संपर्क में आते हैं, तो वे न केवल मीडिया पर बल्कि अपने आसपास के लोगों एवं संस्थाओं पर भी संदेह करने लगते हैं, जिससे सामाजिक एकता प्रभावित होती है।

भारतीय संदर्भ में यह प्रभाव और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2017 से 2018 के दौरान व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों के कारण देश के विभिन्न राज्यों में भीड़ हिंसा की कई घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें अनेक लोगों की मृत्यु हुई। इन घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि झूठी खबरें केवल सूचना का विकृतिकरण नहीं करतीं, बल्कि सीधे तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, फेक न्यूज समाज में भय एवं असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप सामाजिक सौहार्द, पारस्परिक विश्वास एवं स्थिरता कमजोर पड़ जाती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि झूठी खबरें समाज की मूल संरचना को प्रभावित करने वाली एक गंभीर चुनौती हैं, जिनका प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक स्तर पर परिलक्षित होता है।

राजनीतिक प्रभाव झूठी खबरों का राजनीतिक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर। फेक न्यूज मतदाताओं की सोच, दृष्टिकोण और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जिससे चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्यू रिसर्च सेंटर (2016) के अनुसार, 64 प्रतिशत अमेरिकी वयस्कों ने माना कि वे झूठी खबरों के कारण भ्रमित हुए। इसके अतिरिक्त, झूठी खबरें सत्य की तुलना में लगभग 6 गुना तेजी से फैलती हैं, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं में मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावना बढ़ जाती है, जो चुनावी वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तेजी से फैलने वाली गलत सूचनाएँ मतदाताओं तक पहले पहुँच जाती हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। फेक न्यूज का उपयोग कई बार राजनीतिक दलों या हित समूहों द्वारा दुष्प्रचार के रूप में किया जाता है, जिससे मतदाताओं को गुमराह कर अपने पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र की मूल भावनाकृतसत्य, पारदर्शिता और निष्पक्षता, कमजोर पड़ जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि झूठी खबरें केवल सूचना की समस्या नहीं हैं, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती हैं, जिनका प्रभाव दीर्घकाल में राजनीतिक स्थिरता और जनविश्वास दोनों पर पड़ता है।

आर्थिक प्रभाव झूठी खबरों का प्रभाव केवल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक क्षेत्र को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ



ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें भ्रामक सूचनाएँ एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि देखी गई, जो उपभोक्ताओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से आधार और बैंकिंग से संबंधित फर्जी संदेशों के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर उनकी निजी एवं वित्तीय जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कई मामलों में उपयोगकर्ता बिना सत्यापन के ऐसे संदेशों पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे उनके बैंक खातों से धन की चोरी हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, भ्रामक निवेश योजनाएँ, फर्जी ऑनलाइन ऑफर और नकली विज्ञापन भी फेक न्यूज के आर्थिक प्रभाव का हिस्सा हैं। ये योजनाएँ लोगों को त्वरित लाभ का लालच देकर ठगी का शिकार बनाती हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि डिजिटल बाजार और ऑनलाइन लेन-देन के प्रति लोगों का विश्वास भी कमजोर होता है, और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देती है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव वर्तमान डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो गया है, परंतु इसके साथ ही झूठी खबरों की समस्या भी गंभीर रूप धारण कर चुकी है। यह समस्या केवल सूचना की सत्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। प्यू रिसर्च सेंटर (2016) के अनुसार, लगभग 23 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने स्वीकार किया कि वे फेक न्यूज के कारण "काफी हद तक भ्रमित" हुए। यह तथ्य इस बात का संकेत देता है कि भ्रामक सूचनाएँ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संतुलन को प्रभावित करती हैं।

झूठी खबरों से व्यक्ति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है, भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। निरंतर झूठी और नकारात्मक सूचनाओं के संपर्क में रहने से तनाव और मानसिक दबाव बढ़ता है। आधुनिक डिजिटल माध्यमों पर लगातार आने वाली सूचनाएँ व्यक्ति को "सूचना अधिभार" की स्थिति में पहुँचा देती हैं, जिससे मानसिक थकान और चिंता उत्पन्न होती है। यह स्थिति दीर्घकाल में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। साथ ही फेक न्यूज के कारण सामाजिक अविश्वास की भावना भी विकसित होती है। अंततः, इन सभी प्रभावों का समग्र परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में अवसाद, आत्मविश्वास में कमी तथा सामाजिक जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि फेक न्यूज केवल सूचना की त्रुटि नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर मनोवैज्ञानिक चुनौती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ता है।

नियंत्रण एवं समाधान—



वर्तमान डिजिटल युग में भ्रामक सूचना की समस्या एक गंभीर सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है। इसके प्रभावों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इसके नियंत्रण एवं समाधान के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाएँ। सबसे पहले, डिजिटल साक्षरता का विकास अत्यंत आवश्यक है। जब तक आम नागरिकों में सूचना को समझने, परखने और सत्यापित करने की क्षमता विकसित नहीं होगी, तब तक फेक न्यूज का प्रभाव कम नहीं किया जा सकता। लोगों को यह सिखाना होगा कि वे किसी भी समाचार के स्रोत की विश्वसनीयता की जाँच करें और बिना पुष्टि के उसे साझा न करें।

तकनीकी स्तर पर भी प्रभावी समाधान विकसित किए जा रहे हैं। भ्रामक सूचना की पहचान के लिए उन्नत एल्गोरिद्म तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फैक्ट-चेकिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ये तकनीकें संदिग्ध सूचनाओं को चिन्हित कर उनके प्रसार को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। नीतिगत हस्तक्षेप की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को कड़े कानून लागू करने तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उचित नियमन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि गलत सूचना फैलाने वालों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

भारत में झूठी खबरें एवं भ्रामक सूचना के प्रसार का अध्ययन करने में ऑल्ट न्यूज बूम लाइव जैसे सत्यता और प्रामाणिकता की जाँच करनेवाली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया, खबरों या बयानों में फैलाई जा रही फर्जी या भ्रामक खबरों की पहचान करना और उन्हें सच से अलग करना है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट (2017 से 2018) के अनुसार, भारत में वायरल होने वाली भ्रामक सूचनाओं का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक, सांप्रदायिक एवं भावनात्मक विषयों से संबंधित था। बूम लाइव (2018) के विश्लेषण से पता चलता है कि फेक न्यूज के लगभग 60से 70 प्रतिशत मामलों में दृश्य सामग्री का दुरुपयोग किया गया। प्लेटफॉर्म के अनुसार, फेक न्यूज के प्रसार में सोशल मीडिया वित्तकपदह बीपद प्रमुख कारक है, जहां एक संदेश हजारों लोगों तक बिना सत्यापन के पहुँच जाता है। यह डेटा स्पष्ट करता है कि भारत में झूठी खबरों का स्वरूप केवल टेक्स्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मल्टीमीडिया-आधारित भ्रामक संचार के रूप में विकसित हो चुका है।

2018 में भारत में बढ़ती अफवाहों और हिंसा की घटनाओं के बाद व्हाट्सएप ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन लागू किए जैसे एक संदेश को अधिकतम 5 लोगों तक ही फॉरवर्ड करने की सीमा तय की गई,



प्रेषित टैग की शुरुआत उपयोगकर्ता को यह दिखाने के लिए कि संदेश मूल नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड किया गया है साथ समूह प्रेषण को सीमित किया गया साथ ही खुशिया बाटें अफवाह नही जैसे अभियान को चलाया गया।

सामाजिक जागरूकता इस समस्या के समाधान की कुंजी है। मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देकर तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित कर समाज को इस दिशा में सक्रिय बनाना होगा। यदि लोग "सोच-समझकर साझा करें" के सिद्धांत का पालन करें, तो फेक न्यूज का प्रसार स्वतः ही कम हो सकता है। इस प्रकार, फेक न्यूज की समस्या का समाधान केवल तकनीकी या कानूनी उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जागरूक, जिम्मेदार एवं साक्षर समाज का निर्माण आवश्यक है

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि झूठी खबरें एवं भ्रामक सूचना आधुनिक डिजिटल समाज की एक जटिल, बहुआयामी एवं संरचनात्मक समस्या के रूप में उभर चुकी हैं। वर्ष 2018 से पूर्व ही यह प्रवृत्ति वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में गहराई से स्थापित हो चुकी थी, जिसने सामाजिक विश्वास, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा आर्थिक संरचनाओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि झूठी खबरें एवं भ्रामक सूचना केवल सूचना की त्रुटि नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक-मानसिक एवं तकनीकी अंतःक्रिया है, जिसमें डिजिटल साक्षरता की कमी, एल्गोरिदमिक संरचना, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ तथा राजनीतिक हित प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके प्रभाव बहुआयामी है, यह सामाजिक अविश्वास को बढ़ाता है, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को विकृत करता है, आर्थिक धोखाधड़ी को प्रोत्साहित करता है तथा व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। विशेष रूप से युवाओं में बिना सत्यापन के सूचना साझा करने की प्रवृत्ति इस समस्या को और जटिल बनाती है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि झूठी खबरें एवं भ्रामक सूचना केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक संकट है, जिसके समाधान हेतु बहुस्तरीय एवं समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके लिए डिजिटल एवं मीडिया साक्षरता का विस्तार, प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप, उन्नत तकनीकी नियंत्रण तंत्र तथा सामाजिक जागरूकता का विकास अनिवार्य है।



अंततः, एक जागरूक, उत्तरदायी एवं समालोचनात्मक सोच रखने वाला नागरिक समाज ही भ्रामक सूचना के दुष्प्रभावों को नियंत्रित कर सकता है और एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं संतुलित डिजिटल सूचना वातावरण का निर्माण सुनिश्चित कर सकता है।

संदर्भ सूची—

1. Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). *Social media and fake news in the 2016 election*. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211–236.
2. Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). *The spread of true and false news online*. Science, 359(6380), 1146–1151.
3. Pew Research Center. (2016). *Many Americans believe fake news is causing confusion*.
4. UNESCO. (2017). *Journalism, 'Fake News' and Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training*.
5. European Commission. (2018). *A multi-dimensional approach to disinformation*.
6. Internet and Mobile Association of India. (2017). *Internet in India Report*.
7. Telecom Regulatory Authority of India. (2017). *Annual Report 2016–17*.
8. Reserve Bank of India. (2017). *Annual Report 2016–17*.
9. National Sample Survey Office. (2014). *Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India*.
10. Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.
11. Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
12. Hilbert, M. (2011). *Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries?* Women's Studies International Forum, 34(6), 479–489.
13. Gurumurthy, A. (2004). *Gender and ICTs: Overview report*. BRIDGE, IDS.
14. Hafkin, N., & Huyer, S. (2007). *Women and gender in ICT statistics and indicators*. Information Technologies & International Development, 4(2), 25–41.
15. World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*.
16. United Nations Development Programme. (2015). *Human Development Report 2015*.